

SHRI N. C. KASLIWAL: May I know whether in these four States the Government consider the desirability of having mobile units especially to cater to the needs of the people residing in the villages?

DR. SUSHILA NAYAR: Sir, the treatment of trachoma is a very simple thing. What it means is application of a particular ointment for five days in the week, one week in a month, to be repeated for six months. The State of Gujarat has done a magnificent job by organising this programme practically through the efforts of voluntary workers. We have supplied them with the ointment, we have also supplied them with some vehicles, but they are not employing full-time staff for this purpose. Some of the other States wanted some more staff, and according to the pattern worked out with the help of the W.H.O. and UNICEF we have allowed them a certain number of units. Sir, we want to see what will be the result of the voluntary effort as against the effort where we have given full time units and then we shall see how this programme should be taken to the rest of the country.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: The hon. Minister has just said that the treatment of trachoma is going on in four States. May I know whether the hon. Minister has got the number of cases treated in those States, what has been the result, and how many of them have cured?

DR. SUSHILA NAYAR: The treatment is in progress all over the country, in all the States, in all the districts. The regular dispensaries, hospitals, doctors, they give the treatment. In these four States a comprehensive trachoma control programme is being attempted. The number of patients treated, I am afraid, I cannot tell now.

*39. [Withdrawn.]

दिल्ली में झुग्गियों का गिराया जाना

*४०. श्री प्यारे लाल कुरील 'तलिब' : क्या निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में अब तक कुल कितनी झुग्गियां और झोपड़ियां गिराई जा चुकी हैं ;

(ख) जो झुग्गियां और झोपड़ियां गिराई गई हैं उनके एवज में झुग्गी वालों को कितने प्लॉट दिये जा चुके हैं और वे प्लॉट कितने कितने गज के हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने उन्हें सिर्फ २५ वर्ग गज जमीन किराये पर देने का हाल में निश्चय किया है ?

†[DEMOLITION OF JHUGGIES IN DELHI

*40. SHRI P. L. KUREEL URF TALIB: Will the Minister of WORKS, HOUSING AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of jhuggies and Jhonparies demolished so far in Delhi and New Delhi;

(b) the number of plots given to jhuggi-owners in lieu of the demolished jhuggies and jhonparies and the size of each plot in yards;

(c) whether it is a fact that Government have recently decided to give them only 25 square yards of land on rent?]

निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० एस्० नस्कर) :

(क) और (ख) जून, १९६१ से जुलाई, १९६३ तक लगभग ७८०० झुग्गियां गिराई गईं, जिनमें से ७१८२ परिवारों को १६३ मकान, ३६५२ अस्सी वर्ग गज वाले प्लॉट और ३३६७ पच्चीस वर्ग गज वाले

†[] English translation.

प्लाट झुग्गियो और झोपडियो को हटाने की योजना के अन्तर्गत दिये गये ।

(ग) इस योजना में ५००० मकानो, ग्रस्सी वर्ग गज वाले २०,००० विकसित प्लाटो और २५ वर्ग गज वाले २५,००० डेरा डालने के प्लाटो (कैम्पिंग प्लाट्स) की व्याख्या की जानी है ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF WORKS, HOUSING AND REHABILITATION (SHRI P. S. NASKAR) (a) and (b) Between June 1961 and July 1963, about 7800 jhuggies were demolished, out of which 7182 families were allotted 163 tenements, 3652 plots of 80 square yards and 3367 plots of 25 square yards under the Jhuggies and Jhonparies Removal Scheme

(c) The Scheme contemplates the provision of 5000 tenements, 20,000 developed plots of 80 square yards each and 25,000 camping plots of 25 square yards each]

श्री प्यारे लाल कुरील दपटालब :

किया मानल्ले मन्त्री जी को معلوم है कि ये जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं वे अन्ते चहोते हैं कि जहाँ वे जायेंगे उन जगहों पर १० या १५ मकानों के प्लॉट्स बनाने के लिए सरकार को कोई लोन देगी ? या वह खुद उनको बनायेंगे ?

†[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लाट हैं वह इतने छोटे हैं कि झुग्गी वाले जिनके घर में ५ या १० मेम्बर्स होते हैं उनकी इन

प्लाट में कब्र भी नहीं बन सकती है रहना तो दूर रहा । तो क्या इस तरह से गवर्नमेंट स्लम्स को और डवलप करेगी ?]

श्री मेहर चन्द खन्ना माननीय सदस्य ने शायद समझा नहीं । जहाँ तक रहने का ताल्लुक है उसके लिये ८० मुरब्बा गज के प्लाट्स होंगे, लेकिन जहाँ तक कैम्पिंग साइट का ताल्लुक है उसके लिये प्लाट्स सिर्फ २५ मुरब्बा गज के होंगे । मौजूदा झुग्गी और झोपडियो में जितनी जमीन होती है उससे ज्यादा जमीन इन प्लाट्स में है, कम नहीं है ।

श्री प्यारे लाल कुरील दपटालब :

किया ये जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं उनको टम्पोरेरी कैम्प बनाने के लिए सरकार उनको कोई लोन देगी ? या वह खुद उनको बनायेंगे ?

†[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' :

क्या यह जो २५ स्कवायर यार्ड्स के प्लाट हैं उनको टम्पोरेरी कैम्प बनाने के लिए सरकार उनको कोई लोन देगी । या वह खुद उनको बनायेंगे ?]

श्री मेहर चन्द खन्ना जैसे पहले उन्होंने अपनी झुग्गी और झोपडिया बनाई है, वैसे ही अब भी बना ले । न पहले वे कुछ देते थे और न अब गवर्नमेंट कुछ ले रही है ।

श्री प्यारे लाल कुरील दपटालब :

अब जो जगहों को तोड़ा गया और उन जगहों पर लोन देना है - अल्ले अब वे जहाँ से लोन ले लेंगे कि वे खुद जगहों को बनायें ?

†[श्री प्यारे लाल कुरील 'तालिब' : उनकी झुगियों को तोड़ा गया और उनका बहुत नुकसान हुआ। इसलिये अब वह कहां से इतना पैसा लायेंगे कि वह खुद झोंपड़ियां बना लें।]

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह इल्जाम हमारे ऊपर लगाना सरीहन नाजायज़ है। दिल्ली में पचास-साठ हजार झुगी झोंपड़ियां हैं और उनमें न कोई सफाई का इन्तजाम है और न कोई पढ़ाई का इन्तजाम है। दस बारह करोड़ रुपये लगा कर उनको बसाने की योजना बनाई गई है। यह एक अच्छा और नेक काम है और इसमें सब को मदद करनी चाहिये।

شہری پھارے لال کوریل سے مطالبہ ہے :

یہاں جھکی اور چھوٹی والوں کی تعداد لاکھوں ہے - اس لئے چند ہزار پلاٹ دیئے سے یہ پوراہل حل نہیں ہوگی۔ جو ۸۰ اسکوائر بارقس کے پلاٹس ہیں ان پر ممکن بنانے کے لئے سرکار ان کو کوئی لون یا گرانٹ دہکی یا نہیں ؟

†[श्री प्यारे लाल कुरील "तालिब" : यहां झुगी और झोंपड़ी वालों की तादाद लाखों है। इसलिये चन्द हजार प्लाट देने से यह प्रब्लम हल नहीं होगी। यह जो ८० स्क्वायर याड्स के प्लाट्स हैं उन पर मकान बनाने के लिए सरकार उनको कोई लोन या ग्रांट देगी या नहीं ?]

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमने झुगी झोंपड़ियों का बाकायदा दिल्ली में सेंसस लिया है और सेंसस के वक्त जो १९६० में मौजूद थी उनको हमने सिलिप दी है और उनकी तादाद ५० हजार के करीब है।

अब अगर दिल्ली में हर रोज झोंपड़ियां बढ़ती रहें तो यह प्रब्लम कभी साल्व नहीं हो सकती।

SHRI B. K. GAIKWAD: May I know what was the urgency in demolishing the huts of the poor Scheduled Caste people in these rainy days, how far they have been thrown out, and what arrangement has been made for the hutment dwellers there?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: The reasons are simply humanitarian. We have to tackle the problem of their rehabilitation, and I have taken them to proper sites and I shall see that they are properly rehabilitated.

SHRI FARIDUL HAQ ANSARI: May I know whether the hon. Minister has seen in the local press the report that while the jhuggies were being demolished, the people who have been demolishing these jhuggies have also destroyed their belongings?

SHRI MEHR CHAND KHANNA: Sir, three or four operations have taken place recently, and what we do is that we send trucks, we see that the families are properly removed, we see that they are taken to proper sites. Unfortunately the jhuggies have to be demolished, otherwise there is further squatting or resquatting.

شہری پھارے لال کوریل سے مطالبہ ہے :

کوا مانڈیہ ملٹری جی یہ پلاٹس کے کہ جو ۸۰ مربع فٹ کے پلاٹس ہیں یہ الٹھڑ کے نام رجسٹر کئے جائیں گے اور ان کو مالک کا حق دیا جائے ؟

†[श्री प्यारे लाल कुरील "(तालिब)":
क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह
जो ८० मुरब्बा गज के प्लाट्स हैं यह
अलाटीज़ के नाम रजिस्टर किये जायेंगे
और उनको मालिक का हक दिया जायेगा ?]

श्री मेहरचन्द खन्ना जो पैसा
देगा वह मालिक बनेगा और जो पैसा नहीं
देगा वह किरायेदार रहेगा । यह तो हो
नहीं सकता कि सौ-पचास रुपये गज
की जमीन मुफ्त दे दी जाय । अगर
इस तरह से देना शुरू किया तो भगवान के
नाम पर कोई जमीन दिल्ली में नहीं रहेगी ।

REMITTANCE ABROAD OF EARNINGS FROM
FOREIGN FILMS

*41 SHRI A D MANI Will the
Minister of INTERNATIONAL TRADE be
pleased to state the arrangements
under which earnings from foreign
movie films are allowed to be remitted
abroad?

THE MINISTER OF INTERNATIO-
NAL TRADE (SHRI MANUBHAI SHAH)
A statement is laid on the Table of
the House

STATEMENT

Imports of Cinematograph films ex-
posed are mainly effected under ar-
rangements made with the Motion
Pictures Export Association of America
and the Rank Film Distributors of
India Ltd, who are allowed imports
on a 55 per cent quota basis Remit-
tances from net remittable earning
are limited to Rs 10 lakhs per half
year in the case of the former and
Rs 50,000 per half year in the case
of the latter The rest of the net earn-
ings is held under blocked accounts in
India subject to withdrawal for cer-
tain permissive usages like develop-
ing export of Indian films in non-
traditional markets and production of
films in India, with the approval of the
Government of India

SHRI A D MANI I have seen the
statement, and I would like the Min-

ister to explain the import of this sen-
tence "Imports of Cinematograph
films exposed are mainly effected
under arrangements made with the
Motion Pictures Export Association of
America and the Rank Film Distri-
butors of India Ltd, who are allowed
imports on a 55 per cent quota basis"
I understand that the practice in the
film distribuon trade is for some pro-
ducers to insist on 80 per cent of the
net earnings fixed to be sent back to
their countries Does this quota refer
to that or to some other matter?

SHRI MANUBHAI SHAH No, Sir
It is not that When the foreign ex-
change trouble started, we could not
afford to import foreign films because
of the foreign exchange situation So,
we entered into an agreement with
Hollywood, the Motion Pictures Ex-
port Association of America, and the
British film industry, because these
are the only two English speaking
countries from which we import films,
and therefore we fixed the quota at
55 per cent But the remittance which
I have mentioned there is much less,
not more than Rs 10 lakhs per half
year in the case of the United States
and Rs 50,000 per half year in the case
of the Rank Film

SHRI A D MANI I understand fur-
ther that some of the Indian distribu-
tors of these foreign films are allowed
to export films from India to other
Asiatic countries but that under the
arrangements which they have with
the foreign producers, the net foreign
exchange earnings from those coun-
tries are not credited to their Indian
account but to their foreign account
This has been mentioned by the Em-
ployees Union in a statement made to
the Bonus Commissioner Has the at-
tention of the Government been drawn
to that aspect?

SHRI MANUBHAI SHAH This is
a very great menace and we are trying
to tackle it because, when the films
are exported, they go on the net
worth and all the exhibition charges,